जारी/प्र०सु०अनु०१ 11-12-12

संख्याः 1990/43—1—2012

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
(संलग्न सूची के अनुसार)
उत्तर प्रदेश शासन।

जारी 11/12/12

प्रशासनिक सुधार अनुभाग—1 लखनऊ :: दिनांक : 11 ~~नवम्बर~~ Dec, 2012

विषयः— उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति—2012 के प्रस्तर 4.3.3 में उल्लिखित शासकीय प्रक्रियाओं के पुनर्निर्माण (Government Process Reengineering) के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति—2012 जारी की गई है। नीति में दिये गये प्राविधानों पर प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही की जानी है।

2— उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति—2012 के प्रस्तर 4.3.3 के अनुसार :—

"इस नीति का उद्देश्य शासकीय मानकों/प्रकियाओं का पुनर्मूल्यांकन करना है। ताकि शासन रूढ़िगत मार्ग से हटकर नवीन लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु सक्षम हो सकें। शासकीय प्रकियाओं के पुनर्निर्माण को महत्व प्रदान करने के उददेश्य से प्रबन्ध में परिवर्तन (**change management**) के माध्यम से जीटूसी (**G2C**) सेवायें अर्थात् शासनतंत्र को नागरिक उपादेयता के दृष्टिकोण से (**citizen centric**) प्रभावोत्पादक रूप में परिचालित किया जाना होगा।"

3— उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति—2012 के कियावयन के परिप्रेक्ष्य में शासकीय कार्यों, विभागों द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं आदि, में सूचना प्रौद्योगिकी नीति का प्रयोग किया जायेगा जिसके कारण विभागों द्वारा अपनी कार्य प्रकियाओं को पुनर्निर्धारित किया जाना होगा। शासकीय प्रकियाओं के पुनर्निर्माण (Government Process Reengineering) हेतु भारत सरकार की वेबसाइट http://deity.gov.in पर एक हस्तपुस्तिका उपलब्ध है जिसका उपयोग विभागों द्वारा शासकीय कार्य प्रक्रिया के पुनर्निर्माण हेतु किया जा सकता है।

उक्त कम में आपसे यह अनुरोध है कि कृपया प्राथमिकता के आधार पर अपने विभाग की कार्यप्रकिया का पुनर्निर्धारण करायें तथा कृत कार्यवाही से प्रशासनिक सुधार विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

11-12-12
(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि — प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

जन सेवा से जुड़े विभागों की सूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम
1.	कृषि
2.	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
3.	पशुधन
4.	पिछड़ा वर्ग कल्याण
5.	बेसिक शिक्षा
6.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास
7.	कारागार, प्रशासन एवं सुधार
8.	संस्थागत वित्त ,कर एवं निबन्धन
9.	गृह
10.	सहकारिता
11.	दुग्ध
12.	ऊर्जा
13.	आबकारी
14.	मत्स्य
15.	खाद्य एवं रसद
16.	वन
17.	लघु सिंचाई
18.	विकलांग कल्याण
19.	हथकरघा वस्त्र उद्योग
20.	उच्च शिक्षा
21.	आवास एवं शहरी नियोजन
22.	औद्योगिक विकास
23.	सिंचाई
24.	खादी एवं ग्रामोद्योग
25.	श्रम
26.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
27.	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ
28.	पंचायती राज
29.	लोक निर्माण
30.	राजस्व
31.	ग्राम्य विकास
32.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
33.	माध्यमिक शिक्षा
34.	रेशम
35.	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
36.	समाज कल्याण
37.	प्राविधिक शिक्षा
38.	पर्यटन
39.	परिवहन
40.	नगर विकास
41.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
42.	महिला एवं बाल विकास